खंड 5 अंक 9 अप्रैल 2023

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

मार्च 2023 का महीना निस्संदेह महत्वपूर्ण गतिविधियों का समय था, जिसमें रचनात्मक चर्चाएँ, ज्ञान साझाकरण और समावेशी कार्यक्रम शामिल थे। इन प्रयासों ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने, जल प्रबंधन को मजबूत करने और बेहतर भविष्य के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रतिभागियों और संगठनों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

जल संसाधनों में अग्रणी तकनीकी निकाय, केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ), जल संसाधनों के विकास, प्रबंधन, और संबंधित क्षेत्र, के लिए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) और सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग परिषद (सीईडीसी) गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है। के.ज.आ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), द्वारा गठित डब्ल्यूआरडीसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं के अनुरूप मानक विकास पर सलाह देता है। के.ज.आ. भारतीय भागीदारी के साथ आईएसओ तकनीकी समितियों, मार्गदर्शक मानकों का भी नेतृत्व करती है। के.ज.आ के अध्यक्ष के नेतृत्व में, डब्ल्यूआरडीसी ने 17 अनुभागीय समितियों के माध्यम से 465 मानक तैयार किए हैं, जो समय-समय पर अद्यतन या आवश्यकतानुसार परिवर्तन के अधीन हैं। मेरी अध्यक्षता में 06.03.2023 को वर्चुअल मोड में के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली में डब्ल्यूआरडीसी की 21वीं बैठक हुई । बांधों के पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग, हिमानी झील के फटने से बाढ़ (जीएलओएफ), भूस्खलन झील के फटने से बाढ़ का प्रकोप (एलएलओएफ) और शहरी बाढ़ के लिए नई अनुभागीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया। नई आईएसओ समिति छोटे जल विद्युत संयंत्र (आईएसओ / टीसी 339)में भारत की भाग लेने वाली 'पी' सदस्यता को स्वीकार करने की मंजूरी दी गई।

गांधीनगर, गुजरात ने 27-29 मार्च, 2023 तक दूसरी जी20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक की मेजबानी की। यह वैश्विक सभा भूमि क्षरण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और जैव विविधता संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित थी। बैठक में, 19 से अधिक जी20 सदस्य देशों, नौ आमंत्रित देशों और 13 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि एकत्र हुए, जो 130-प्रतिनिधियों के आंकड़े को पार कर गए। कार्यक्रम की शुरुआत सुश्री देबाश्री मुखर्जी विशेष सचिव, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण के साथ हुई।

जलशक्ति मंत्रालय के मंडप में गुजरात सरकार के एक स्टॉल के साथ-साथ विभिन्न संगठनों की जानकारी और योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले 15 स्टॉल शामिल हैं। के.ज.आ के डीआरआईपी स्टॉल ने जलवायु-स्थिति-स्थापक बांधों और समुदायों, बांध परिसंपत्ति के जीवन विस्तार और बांध सुरक्षा अधिनियम में योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एजेंडा-2023 के साथ संरेखित करने पर जोर दिया गया। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में माही एंड तापी बेसिन संगठन(एमटीबीओ), के.ज.आ , गांधीनगर ने कार्यक्रमों के आयोजन और साइट विजिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केंद्रीय जल आयोग निष्पक्षता, तकनीकी विशेषज्ञता और न्यायसंगत संसाधन आवंटन के माध्यम सेअंतरराज्यीय जल मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहयोग को बढ़ावा देता है, संघर्षों को रोकता है और नदी बेसिन साझा करने वाले राज्यों के बीच स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है। मार्च 2023 में, सीडब्ल्यूसी ने नोहर फीडर, बरूवाली वितरिकाओं, मुल्लापेरियार बांध और गोदावरी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर बैठकें आयोजित कीं। सीडब्ल्यूसी अधिकारियों ने पोलावरम सिंचाई, वेस्ट सेटी एचईपी, सोम्ब सरस्वती बैराज, लखवार एमपीपी, रेओली दुगली एचईपी और रेणुका बांध परियोजना जैसी परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और मूल्यवान इनपुट भी प्रदान किए, जिससे परियोजना अधिकारियों और हितधारकों को लाभ हुआ।

तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) ने 1991 में एक उच्च स्तरीय अंतर-विषयक आधिकारिक निकाय, "नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर्स (एनसीएसडीपी) पर राष्ट्रीय समिति" (जिसे पहले स्थायी समिति के रूप में जाना जाता था) का गठन किया था, जो

नदी घाटी परियोजनाओं के बांधों और अन्य सहायक संरचनाओं के डिजाइन हेतु साइट विशिष्ट डिजाइन भूकंपीय मापदंडों की सिफारिश करती थी। भूकंपीय मापदंडों के निर्धारण के लिए साइट विशिष्ट रिपोर्ट में या तो नियतात्मक भूकंपीय खतरा विश्लेषण (डीएसएचए) विधि या संभाव्य भूकंपीय खतरा विश्लेषण (पीएसएचए) विधि का उपयोग करके भूकंपीय मापदंडों का अनुमान शामिल होता है। इस संबंध में, सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में एनसीएसडीपी की 37वीं बैठक 10.03.2023 को आयोजित की गई थी। साइट विशिष्ट भूकंपीय डिजाइन मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए पांच परियोजनाओं और एक सूक्ष्म भूकंप अध्ययन पर विचार किया गया।

आईआईटी रूड़की में भारतीय जल संसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) और जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग के सहयोग से "भविष्य की सुरक्षा के लिए खेत जल प्रबंधन" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला ने देश की भविष्य की जल, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा पर जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर में 143 जलाशयों के वास्तविक समय के भंडारण स्तर की निगरानी करता था, हर गुरुवार को एक बुलेटिन जारी करता था। मार्च 2023 में उनके निगरानी प्रयासों का विस्तार उल्लेखनीय है, क्योंकि तीन और जलाशयों- पानशेत (तानाजीसागर), भामा आस्केड और दरना बांध को शामिल किया गया, जिससे निगरानी किए गए जलाशयों की कुल संख्या 146 हो गई।

हमारे सांस्कृतिक मूल्य महिला सशक्तिकरण को मजबूती से कायम रखते हैं। अपने संगठन के भीतर, हम समानता और समर्थन का माहौल विकसित करते हैं। यह प्रतिबद्धता हमारी व्यापक नीतियों, मार्गदर्शन पहलों और नेतृत्व व पेशेवर विकास को बढ़ावा देने वाले प्रयासों से स्पष्ट है। 08.03.2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगठन में चारों ओर की ऊर्जा वास्तव में स्फूर्तिदायक थी।

"अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस- महिला सशक्तिकरण" कार्यशाला के एक हिस्से के रूप में, सुश्री देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की उपस्थिति में, 06.03.2023 को कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान, निपुण महिला अधिकारियों ने अपने सीडब्ल्यूसी अनुभवों को साझा किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा उन महिला अधिकारियों के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिन्होंने सीडब्ल्यूसी को 35 वर्षों से अधिक की सेवा समर्पित की है। इसके अतिरिक्त, 03.03.2023 को आयोजित ड्राइंग, पेंटिंग और रंगोली बनाने वाले प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

विषयसूची

- बीआईएस की जलसंसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) की 21वीं बैठक
- गोदावरी बेसिन और उसके उप बेसिनों में जल उपलब्धता के आकलन के लिए बैठक
- भूकंपीय डिज़ाइन पैरामीटर्स पर राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) की 37वीं बैठक
- राजस्थान को नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से कम पानी मिलने के मुद्दे पर बैठक
- द्वितीय रावी ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर की प्रगति पर चर्चा
- 25वीं कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की 74वीं आईईसी के लिए आयोजन समिति की दूसरी बैठक
- मुल्लापेरियार बांध (एमपीडी) पर पर्यवेक्षी समिति की 16वीं बैठक
- गांधीनगर, गुजरात में जी-20 जल प्रतिनिधि प्रदर्शनी
- पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना के लिए बैराज और बांध विकल्प की समीक्षा के लिए आठ सदस्यीय अंतर-सरकारी समूह की तीसरी बैठक
- झारखंड और बिहार में उत्तरी कोयल परियोजना के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) पर विचार के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठक
- परियोजनाओं के संबंध में बैठकें
- "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-महिला सशक्तिकरण" पर कार्यशाला
- "भविष्य की सुरक्षा के लिए कृषिक्षेत्र जल प्रबंधन" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- काया घाटी सिंचाई परियोजना, अरुणाचल प्रदेश
- सरदार सरोवर बांध, गुजरात
- पूर्ण एमएमआई/एसएमआई/आरआरआर सिंचाई परियोजना में कमांड क्षेत्र के विकास कार्यों के आधुनिकीकरण पर प्रस्तावित केंद्रीय प्रायोजित उप-योजना (पीएमजीकेएवाई) पर आंतरिक परामर्श
- केंद्रीय जल आयोग एवं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राजभाषा हिंदी संगोष्ठी
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
- हिन्दी कार्यशाला का आयोजन
- जलाशय निगरानी
- योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- इतिहास- सारदा सहायक परियोजना - पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान।

बीआईएस की जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) की 21वीं बैठक

बीआईएस की जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) के अध्यक्ष के रूप में श्री कुश्विन्दर वोहरा अध्यक्ष, के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में डब्ल्यूआरडीसी की 21वीं बैठक 06.03.2023 को के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी।

बैठक में जल संसाधन क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रभाग परिषद के सदस्यों/पदेन सदस्यों के रूप में भाग लिया। डब्ल्यूआरडीसी में 06 अनुभागीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में मुख्य अभियंताओं के अलावा 17 अनुभागीय समितियों के सदस्यों के रूप में अन्य निदेशकों द्वारा केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व किया गया।

बैठक के दौरान, अध्यक्ष ने बांधों के पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड (एलएलओएफ) और शहरी बाढ़ जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए मानकीकरण पर जोर दिया। उपरोक्त क्षेत्रों के लिए नई अनुभागीय समिति बनाने और मौजूदा अनुभागीय समितियों से अतिव्यापी क्षेत्रों को अलग करने का निर्णय लिया गया।
नए विषय क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई आईएसओ समिति लघु जलविद्युत संयंत्रों (आईएसओ/टीसी339) में

भारत की प्रतिभागी 'पी' सदस्यता को स्वीकार करने को भी मंजूरी दी गई।

अध्यक्ष ने बीआईएस सचिवालय को परिषद द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाली एक खोज समिति के माध्यम से अनुभागीय समितियों की गतिविधियों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

गोदावरी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में पानी की उपलब्धता के आकलन के संबंध में बैठक

गोदावरी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में पानी की उपलब्धता के आकलन के संबंध में बैठक 09.03.2022 को सदस्य (डी एंड आर) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और एचएसओ इकाई के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्ष, जीआरएमबी ने के.ज.आ से जीडब्ल्यूडीटी पुरस्कार के अनुसार गोदावरी बेसिन की जल उपलब्धता पर एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है।

भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर्स पर राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) की 37वीं बैठक

भूकंपीय डिजाइन मापदंडों पर राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) की 37वीं बैठक श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) की अध्यक्षता में 10.03.2023 को के.ज.आ, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें 5 परियोजनाओं पर साइट विशिष्ट भूकंपीय डिजाइन मापदंडों को अंतिम रूप देने और 1 सूक्ष्म भूकंप अध्ययन पर समिति के अनुमोदन के लिए विचार किया गया। बैठक में दो परियोजनाओं (पांच में से) को मंजूरी दे दी गई और 1 सूक्ष्म भूकंप अध्ययन को स्वीकार कर लिया गया। बैठक में गुणन कारकों और (आई/आर) मूल्यों को अंतिम रूप देने और एनसीएसडीपी दिशानिर्देश की समीक्षा पर भी चर्चा की गई।

पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं समृतम्।
पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिर्भवति पाण्डव।
पानीयस्य गुणा दिव्याः परलोके गुणावहाः।।

महाभारत में कहा गया है कि संसार में जल से ही समस्त प्राणियों को जीवन मिलता है। जल का दान करने से प्राणियों की तृप्ति होती है। जल में अनेक दिव्य गुण हैं। ये गुण परलोक में भी लाभ प्रदान करते हैं-

राजस्थान को नोहर फीडर और बरूवाली वितरिकाओं से कम पानी मिलने के मुद्दे पर बैठक

श्री कुश्विन्दर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और पदेन सचिव, भारत सरकार ने नोहर फीडर और बरूवाली वितरिका से राजस्थान को पानी की कम उपलब्धता के मुद्दे के संबंध में 02.02.2023 को हुई पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राजस्थान,हरियाणा और बीबीएमबी के जल संसाधन/सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस/वर्चुअल मोड के माध्यम से 15.03.2023 को एक बैठक की।

बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

- आई एंड डब्ल्यू आर डी, हरियाणा और डब्ल्यूआरडी, राजस्थान आपसी परामर्श से नहर प्रणाली के सुधार जैसे कि नोहर फीडर, बरूवाली वितरिका, फतेहाबाद शाखा, कॉमन पूल (सीपी-4), नेहराणा हेड, क्रॉस रेगुलेटर आदि की मरम्मत/रीमॉडलिंग के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प की डीपीआर तैयार करेंगे । प्रारंभिक वैचारिक योजना 23.04.2023 तक के.ज.आ. को सूचित की जा सकती है। लाभ और लागत के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए डीपीआर तैयार करने का कार्य समानांतर रूप से जारी रखा जा सकता है। डीपीआर जमा करने की समयसीमा अगली समीक्षा बैठक के दौरान तय की जाएगी। दोनों राज्य

आपसी सहमति से डीपीआर तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं।

- प्रणाली को आवश्यकता की सीमा तक ही आधुनिक बनाया जाए। प्रस्ताव की लागत को इस तरह से अनुकूलित किया जाना चाहिए कि इसमें केवल वे घटक/आइटम शामिल हों जो प्रणाली के सुधार के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं।

के.ज.आ. द्वारा निर्वहन माप पर रिपोर्ट को 15.04.2023 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। के.ज.आ. तुरंत बीबीएमबी के साथ डिस्चार्ज माप का विवरण साझा करेगा; और बीबीएमबी इसका विश्लेषण करेगा और अगली बैठक के दौरान बीबीएमबी प्रणाली में सुधार की संभावना बताएगा।

द्वितीय रावी ब्यास लिंक परियोजना के पीएफआर की प्रगति पर चर्चा

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परियोजनाओं को सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट(पीएफआर) चरण में है। रावी और ब्यास/सतलुज के बीच लिंक द्वारा गुरुत्वाकर्षण के तहत गैर-मानसूनी अवधि में सीमा पार बहने वाले पानी (लगभग 0.58 एमएएफ) का दोहन करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।

के.ज.आ. के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में 20.02.2023 को आयोजित बैठक के दौरान की गई चर्चा की अनुवर्ती के रूप में, दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना के विभिन्न विकल्पों पर पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक और बैठक 16.03.2023 को के.ज.आ. (मुख्यालय), नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ., सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., डब्ल्यूआरडी के अधिकारी, पंजाब सरकार (जीओपी), केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी और अन्य संबंधित संगठनों ने भाग लिया। बैठक

के दौरान डब्ल्यूआरडी, गोएपी द्वारा प्रस्तुत संशोधित रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने डब्ल्यूआरडी, जीओपी के अधिकारियों को नवीनतम एसओआर, डब्ल्यूआरडी, जीओपी की आवश्यकता और अन्य महत्वपूर्ण विचारों के अनुसार 14.03.2023 को जीओपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को और संशोधित करने और तदनुसार, रिपोर्ट को फिर से जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने आईबीओ, के.ज.आ., चंडीगढ़ में तैनात के.ज.आ. निदेशकों को यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने और सीई (आईबीओ), के.ज.आ. को प्रगति की निगरानी करने का भी निर्देश दिया।

25वीं कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की 74वीं आईईसी के लिए आयोजन समिति की दूसरी बैठक

25वीं कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की 74वीं आईईसी की आयोजन समिति की दूसरी बैठक 23.03.2023 को हाइब्रिड मोड में के.ज.आ./भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के अध्यक्ष श्री कुश्विन्दर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ., भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति , अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने आयोजन स्थल को अंतिम रूप देने, कार्यक्रम के लिए समय-सारणी,समितियों, प्रदर्शनी आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, आयोजन समिति ने कांग्रेस और आईईसी बैठक स्थल के लिए अंतिम रूप में रेडिसन ब्लू रिसॉर्ट, विजाग को चुना। समिति को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को INCID सचिवालय के प्रस्ताव के साथ-साथ आयोजन के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए गठित की जा रही विभिन्न समितियों के दायरे और संरचना के बारे में सूचित किया गया। समिति ने इवेंट वेबसाइट के अद्यतनीकरण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की भागीदारी से संबंधित घटनाक्रम पर भी गौर किया। समिति ने कुछ समावेशन, विलोपन सहित पदनामों में बदलाव के साथ-साथ आयोजन समिति की सदस्यता की भी समीक्षा की।

मुल्लापेरियार बांध (एमपीडी) पर पर्यवेक्षी समिति की 16वीं बैठक

मुल्लापेरियार बांध (एमपीडी) पर पर्यवेक्षी समिति की 16वीं बैठक 27.03.2023 को श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा संगठन, के.ज.आ और अध्यक्ष एमपीडी कुमिली, केरल की पर्यवेक्षी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया; डॉ.संदीप सक्सेना, एसीएस,डब्ल्यूआरडी,तमिलनाडु सरकार, डॉ.वी. वेणु, एसीएस, डब्ल्यूआरडी, केरल सरकार, श्री आर सुब्रमण्यन, अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू, तमिलनाडु सरकार, और श्री एलेक्स वर्गीस, मुख्य अभियंता (आई एंड ए) सिंचाई विभाग, केरल सरकार और के.ज.आ, तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार के अन्य अधिकारी। पर्यवेक्षी समिति ने पूर्वाह्न में वल्लाकादावु घाट रोड और मुल्लापेरियार बांध और उससे जुड़ी संरचनाओं के पूरे हिस्से का निरीक्षण किया। दृश्य निरीक्षण से पता चला कि बांध और उससे जुड़ी संरचनाओं की समग्र स्थिति समिति द्वारा संतोषजनक पाई गई।

गांधीनगर, गुजरात में जी-20 जल प्रतिनिधि प्रदर्शनी

के.ज.आ के निदेशक श्री आर.के.गौतम ने 27-29 मार्च 2023 के दौरान गांधीनगर, गुजरात में आयोजित जी-20 देशों की पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक के दौरान प्रदर्शक के रूप में भाग लिया। जल शक्ति मंत्रालय के 15 स्टॉलों में से डीआरआईपी स्टॉल भी एक था।

डीआरआईपी स्टॉल ने बांधों और समुदायों के जीवन को बढ़ाकर, भोजन, ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, जलवायु अनुकूल बांधों और समुदायों के प्रति सकारात्मक योगदान की कहानी पर प्रकाश डाला। स्टॉल में हाल ही में लागू बांध सुरक्षा अधिनियम के बारे में भी प्रदर्शन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एजेंडा 2023 के प्रति कार्यक्रम के योगदान पर भी जोर दिया गया।

आमंत्रित विदेशी प्रतिनिधियों, एमओईएफ एंड सीसी, एमओजेएस, के.ज.आ, गुजरात सरकार आदि के अधिकारियों ने स्टालों का दौरा किया।

आगंतुकों को परियोजना के बारे में समझाया गया, और स्थायी रूप से इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए जल संरचना के सुरक्षित रखरखाव के लिए इसकी प्रासंगिकता बताई गई।

पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना के लिए बैराज और बांध विकल्प की समीक्षा के लिए आठ सदस्यीय अंतर-सरकारी समूह की तीसरी बैठक

आठ सदस्यीय अंतर सरकारी समूह (आईजीजी) ने 28.03.2023 को नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की। सदस्य, डी एंड आर ने इस बैठक में भाग लिया। अन्य प्रतिभागियों में आईजीजी के अध्यक्ष, सभी आईजीजी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, एनजीआई और फिचनर के विशेषज्ञ शामिल थे। बैठक के दौरान पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना (पीएचईपी-I) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

झारखंड और बिहार में उत्तरी कोयल परियोजना के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) पर विचार के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठक

वित्त सचिव एवं सचिव(व्यय) की अध्यक्षता में 31.03.2023 को नॉर्थ ब्लॉक,वित्त मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड और बिहार में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की आरसीई पर विचार करने के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक आयोजित की गई थी।

आयुक्त (एफएम), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने पीआईबी के विचारार्थ प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। पीआईबी ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के आरसीई के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और उसे स्वीकार किया।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पोलावरम बैठक

मार्च 2023 के दौरान, पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं। ईसीआरएफ डैम गैप-II की डायाफ्राम दीवार के स्वास्थ्य मूल्यांकन पर चर्चा के लिए, के.ज.आ डिजाइन टीम और एनएचपीसी अधिकारियों को शामिल करते हुए, श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) की अध्यक्षता में 02.03.2023 को एक बैठक हुई।

05.03.2023 को, परियोजना के लिए बांध डिजाइन समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) की 21वीं बैठक श्री ए.बी.पांड्या की अध्यक्षता में राजमुंदरी में हुई। बैठक में के.ज.आ , सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस, पीपीए, डब्ल्यूआरडी, जीओएपी, एनएचपीसी और डब्ल्यूएपीसीओएस सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चाएं डिजाइन के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जैसे गैप-I और II पर ईसीआरएफ बांध की जर्जर नींव में रेत भरने के तरीके, गैप-II पर क्षतिग्रस्त डायाफ्राम दीवार के लिए सुधार के उपाय, अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध से रिसाव के मुद्दे, डीवाटरिंग, उपागम वाहिका पर सीडब्ल्यूपीआरएस मॉडल अध्ययन रिपोर्ट और ट्रूनियन बीम पर गैर-विनाशकारी परीक्षण। इस बैठक के दौरान रेत भरने की विधि और गैप-II डायाफ्राम दीवार पर निर्णय लिए गए।

आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 09.03.2023 को एक और बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय जल आयोग, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्रदान की। चर्चा में अर्थ-कम रॉक फिल (ईसीआरएफ) ¡बांध की निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने और लाभ/लागत (बी/सी) अनुपात जैसे लंबित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई और समयसीमा पर भी चर्चा हुई। डब्ल्यूआरडी, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने अर्थ-कम रॉक फिल (ईसीआरएफ) बांधों के संबंध में विभिन्न कार्यों और डिजाइन से संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अंततः आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13.03.2023 को एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिव डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस और जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री के सलाहकार के साथ श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य(डी एंड आर), ने भाग लिया।

वेस्ट सेती एचईपी, परियोजना

वेस्ट सेती एचईपी, नेपाल के लेआउट के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 03.03.2023 को के.ज.आ में एनएचपीसी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। परियोजना की प्रकृति, बांध की लागत को अनुकूलित करने के तरीकों, भूमिगत पावर हाउस के प्रस्तावित स्थान पर समस्याओं और आवंटित नदी पहुंच का पूरा उपयोग करने की संभावनाओं से संबंधित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

सोंब सरस्वती बैराज परियोजना

सोम्ब सरस्वती बैराज से सरस्वती जलाशय तक परिवहन पाइपलाइन के वैकल्पिक लेआउट पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ और एचएसएचडीबी अधिकारियों की 10.03.2023 को बैठक हुई। परियोजना प्राधिकारियों को लेआउट विकल्पों को चार से घटाकर दो करने और उनके बारे में विस्तार से बताने की सलाह दी गई।

लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना (300 मेगावाट), उत्तराखंड

लखवार एमपीपी, उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 15.03.2023 को सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में के.ज.आ और यूजेवीएन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। भूवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने के लिए विशेषज्ञों के एक भूविज्ञानी समूह (जीजीई) के गठन और एनआईआरएम द्वारा किए गए संख्यात्मक अध्ययनों की समीक्षा करने के लिए तकनीकी समूह और बिजलीघर परिसर के उत्खनन कार्यों से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई है।

रेओली डुगली जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश

रेओली डुगली एचई परियोजना के प्रस्तावित सर्ज शाफ्ट का व्यास असामान्य रूप से बड़ा है और निष्पादन के दौरान स्थिरता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। तदनुसार, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) के कार्यालय में 16.03.2023 को सीईए, के.ज.आ , जीएसआई और एसजेवीएन अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक के दौरान प्रस्तावित वैकल्पिक भूमिगत संरचनाओं के असाधारण बड़े आकार के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

रेणुकाजी बांध परियोजना

श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में 03.03.2023 को वर्चुअल मोड में रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश के भूविज्ञानी विशेषज्ञों के पैनल के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पैनल के सदस्यों के अलावा के.ज.आ , जीएसआई, सीएसएमआरएस और एचपीपीसीएल के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान बांध स्थल पर भूविज्ञान, बांध के प्रकार, स्पिलवे के प्रकार और परियोजना में अवसादन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला/प्रस्तुतिया

"अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-महिला सशक्तिकरण" पर कार्यशाला

08.03.2023 अर्थात, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक भाग के रूप में, के.ज.आ (मुख्यालय)ने 06.03.2023 को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-महिला सशक्तिकरण" पर एक कार्यशाला आयोजित की, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सुश्री देबाश्री मुखर्जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर दिन महिला दिवस है। जहां तक महिलाओं के रोजगार का सवाल है, 19% महिलाएं श्रमिक हैं। उन्होंने महिला अधिकारियों को सलाह दी कि यदि उनके पास योगदान करने के लिए कुछ है, तो उन्हें बोलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी जाए, भले ही कमरे में केवल एक महिला ही क्यों न हो। इसके अलावा, महिलाओं को काम पर आने वाली महिलाओं के साथ अपना नेटवर्क बनाना चाहिए, उन्हें सलाह देनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब भी मौका मिले, सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाएं, इससे लंबे समय में बड़ा बदलाव आएगा। के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुश्विन्दर वोहरा ने अपना संबोधन दिया और कहा कि नारीशक्ति परिवार, समाज और देश का पोषण करती है। इसके अलावा, नारीशक्ति संगठन में आवश्यक संतुलन प्रदान करके, नए रास्ते और रचनात्मक तरीकों की खोज करके एक संगठन का पोषण भी करती है।

इसके बाद महिला अधिकारियों ने के.ज.आ में अपने अनुभव साझा किए, इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा उन महिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने के.ज.आ में 35 वर्ष से अधिक की लंबी सेवा की है।

03.03.2023 को आयोजित ड्राइंग, पेंटिंग और रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।

"भविष्य की सुरक्षा के लिए कृषिक्षेत्र जल प्रबंधन" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

के.ज.आ ने 20.03.2022 को भारतीय जलसंसाधन सोसायटी (आईडब्ल्यूआरएस) और जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग, आईआईटी रूड़की के सहयोग से "भविष्य की सुरक्षा के लिए कृषिक्षेत्र जल प्रबंधन" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की।

के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुश्विन्दर वोहरा, जो आईडब्ल्यूआरएस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने देश की भविष्य की जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डाला। जब तक जल उपयोग दक्षता और फसल उत्पादकता में सुधार के उपाय नहीं अपनाए जाते, तब तक कृषि क्षेत्र के प्रमुख उपभोक्ता होने के कारण काफी प्रभावित होने की उम्मीद है। उन्होंने दर्शकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा पहले ही अपनाई गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया।

अध्यक्ष, के.ज.आ ने सभी शिक्षाविदों, पेशेवरों और अभ्यास करने वाले इंजीनियरों सहित प्रतिभागियों के बीच उक्त विषय पर सार्थक विचार-विमर्श आयोजित करने के लिए कार्यशाला की सफलता पर बधाई दी।

बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (धर्मा) पर प्रशिक्षण

डीआरआईपी-2 के तहत क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, सीपीएमयू वर्चुअल मोड में धर्मा पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ड्रिप-II कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए धर्मा पोर्टल पर चौथा प्रशिक्षण 29.03.2023 को आयोजित किया गया था प्रशिक्षण में एसडीएसओ के अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के बांध प्रबंधकों ने भाग लिया।

के.ज.आ अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/साइटों का दौरा/निरीक्षण

काया घाटी सिंचाई परियोजना, अरुणाचल प्रदेश

23 से 27 मार्च 2023 के दौरान बीसीडी (ई एंड एनई) निदेशालय, के.ज.आ , जल विज्ञान (एनई) निदेशालय, के.ज.आ के अधिकारियों के साथ बीबीओ, के.ज.आ , गुवाहाटी, जीएसआई, शिलांग और सिंचाई विभाग, असम सरकार के अधिकारियों द्वारा काया घाटी सिंचाई परियोजना, अरुणाचल प्रदेश का संयुक्त क्षेत्र दौरा किया गया। संयुक्त दौरे का उद्देश्य क्षेत्र की स्थितियों का आकलन करना था ताकि विभिन्न डिजाइन पहलुओं पर संभावित और उपयुक्त बैराज एक्सिस और कमांड क्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा सके।

काया घाटी सिंचाई योजनाएँ एक लघु सिंचाई योजना है जो थ्रिज़िनो सिविल सब-डिवीजन के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। इस योजना के तहत अस्थायी सकल कमांड क्षेत्र 480.70 हेक्टेयर होगा। संपूर्ण कमांड क्षेत्र को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है और डेस्कटॉप अध्ययन के अनुसार दो अलग-अलग बैराज प्रस्तावित हैं। बैराज 1 पर धारा प्रवाह (स्थानीय नदी) में योगदान देने वाला कुल जलग्रहण क्षेत्र 101.638 वर्गकिमी है और बैराज 2 पर 215.363 वर्गकिमी है। यह योजना कमांड क्षेत्र की सिंचाई और घरेलू पानी की आवश्यकता को पूरा करेगी।

सरदार सरोवर बांध, गुजरात

श्री सतीश कंबोज, निदेशक, गेट्स डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) डीटीई, के.ज.आ और श्री घनश्याम पटेल, उप निदेशक, गेट्स डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) डीटीई, के.ज.आ   ने परियोजना अधिकारियों के साथ 24.03.2023 और 25.03.2023 को सरदार सरोवर बांध, गुजरात का दौरा किया, जिसमें स्टॉपलॉग, लिफ्टिंग बीम और सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात के 100टी स्पिलवे गैन्ट्री क्रेन आरबीपीएच के रोप वाइंडिंग के संचालन के दौरान परियोजना अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया।

पूर्ण एमएमआई/एसएमआई/आरआरआर सिंचाई परियोजना में कृषि क्षेत्र के विकास कार्यों के आधुनिकीकरण पर प्रस्तावित केंद्रीय प्रायोजित उप-योजना (पीएमएसकेएयू) पर आंतरिक परामर्श

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग पहले से ही स्वीकृत पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएमएस योजना के एक उप घटक के रूप में कृषि क्षेत्र के विकास कार्यों के आधुनिकीकरण (प्रधानमंत्री सिंचाई क्षेत्र आधुनिकीकरण उपाय) के लिए एक उप योजना की परिकल्पना कर रहा है। उप योजना को पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम की संभावित बचत से संचालित करने का प्रस्ताव है। उप योजना की कल्पना आपूर्ति नेटवर्क और संचार प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के व्यापक उपयोग के साथ की गई है। भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई नेटवर्क के साथ स्थापित स्रोत से फार्म गेट तक 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई प्रस्तावित है और वॉल्यूमेट्रिक माप के लिए आईओटी/एससीएडीए जैसी स्थापित संचार प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग-जैसे बुनियादी ढांचे की जियोटैगिंग और जीआईएसकमांड क्षेत्र मैपिंग, ऐप आधारित नियंत्रण, एमआईएस पोर्टल, नॉलेजटूल किट आदि । प्रस्तावित स्वामित्व और नियंत्रण जल उपयोगकर्ता सोसायटी के माध्यम से होगा। प्रस्तावित उपयोजना के कार्यान्वयन के बाद लगभग 50 बीसीएम पानी की अपेक्षित बचत होगी। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सीएडीडब्ल्यूएम विंग को सुझाव/टिप्पणियां/टिप्पणियां पेश की हैं। मुख्य सुझाव/टिप्पणियाँ/टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं।

- सुझाव दिया गया है कि 100% दबावयुक्त पाइप सिंचाई सीएडीडब्लूएम का निष्पादन बड़े पैमाने पर शुरू करने से पहले क्षेत्र-वार पायलट आधार पर किया जा सकता है। इससे लाभ में बढ़ोतरी का आकलन करने में मदद मिलेगी।
- मौजूदा गुरुत्व क्षेत्र चैनलों सिंचित कमांड को दबावयुक्त पाइप सिंचाई कमांड में बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन असंभव नहीं है।
- पीपीपी मोड की शुरूआत, प्रोत्साहन और उपयोगकर्ताओं के बीच व्यापक जागरूकता कार्यक्रम सहित तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाकर परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है।
- निजी क्षेत्र को शासन, निवेश संचालन, सिंचाई सेवाओं के रखरखाव और प्रबंधन में पीपीपी मोड पर शामिल किया जा सकता है।
- ड्रिप सिंचाई के संबंध में धान और गन्ना किसानों के बीच एक भ्रांति है। एक विशेषज्ञ की राय किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित की जा सकती है। सफलता की कहानी विकसित करने के लिए धान और गन्ना उगाए जाने वाले क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक पायलट परियोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

उपज में वृद्धि आदि सहित लागत और लाभ के पहलुओं पर अधिक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि जैसे प्रमुख राज्यों को शामिल करने की आवश्यकता है जिन्होंने बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई लागू की है।

केंद्रीय जल आयोग एवं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राजभाषा हिंदी संगोष्ठी

दिनांक 17 मार्च 2023 को केंद्रीय जल आयोग एवं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के तत्वाधान में केंद्रीय जल आयोग के सभागार में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

हिंदी भाषा की सरलता एवं सुगमता को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यशाला में काव्य पाठ तथा भाषणों के माध्यम का सहारा लिया गया ताकि उपस्थित कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। माननीय डॉ. भगवान दास पटैरया, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति ने भी इस संबंध में अपना संबोधन दिया।

माननीय श्री कुश्विन्दर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं भारत सरकार के पदेन सचिव द्वारा संबोधन के दौरान राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य के लिए सभी कर्मचारियों के मनोबल को बढाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर बल दिया कि कार्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रसार करने के लिए कठिन भाषा या शब्द लिखने या जानने के बदले दैनिक रूप से बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए और एक नियमित अभ्यास के तहत अपनी दैनिक कार्यालयी दिनचर्या में लाया जाए।

उन्होने यह भी अपील किया कि सभी कर्मचारी एक संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ दृढ निश्चय से राजभाषा हिंदी में तन-मन से बढ़ चढ़ कर कार्य करें ताकि न केवल राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अपने गौरव को और भी बढाने हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से केंद्रीय जल आयोग को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त किया जा सके।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

दिनांक 31.03.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 151वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सितंबर, 2022 एवं दिसंबर, 2022 की तिमाही रिपोर्ट की तुलनात्मक समीक्षा की गई एवं सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के दौरान अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए समुचित दिशानिर्देश दिए गए। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय तत्काल आधार पर करने का निदेश दिया।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 03.03.2023 को केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. शोभा रानी, संयुक्त निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा "राजभाषा कार्यान्वयन में हिन्दी प्रशिक्षण का योगदान" विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस कार्यशाला में आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को व्याख्याता द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण के महत्व एवं इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया।

जलाशय निगरानी

के.ज.आ के जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली (आरएसएमएस) में मार्च 2023 के महीने में नीचे नामित तीन और जलाशय जोड़े गए हैं।

जलाशय का नाम	राज्य	सजीव भंडारण क्षमता
पानशेत (तानाजीसागर)	महाराष्ट्र	0.302 बीसीएम
भामा आस्केड	महाराष्ट्र	0.217 बीसीएम
दरना बांध	महाराष्ट्र	0.202 बीसीएम
	कुल=	0.721 बीसीएम

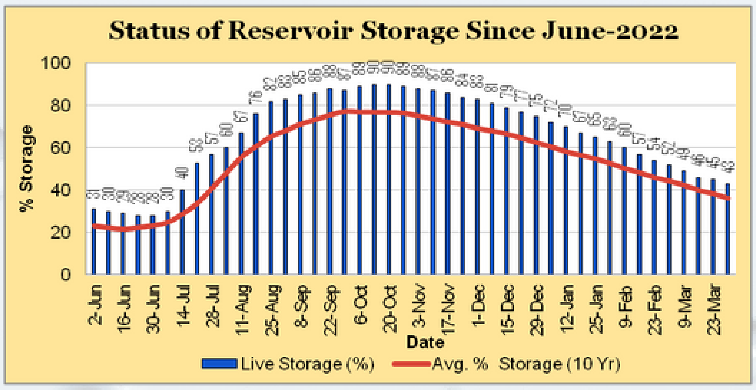

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 146 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 34.960 बीसीएम है। इन 146 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 178.185 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 69.11% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 31.03.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 76.058 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 43% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 81.19 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 64.534 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2023 के बुलेटिन के अनुसार 146 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 94% प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 118 प्रतिशत है।

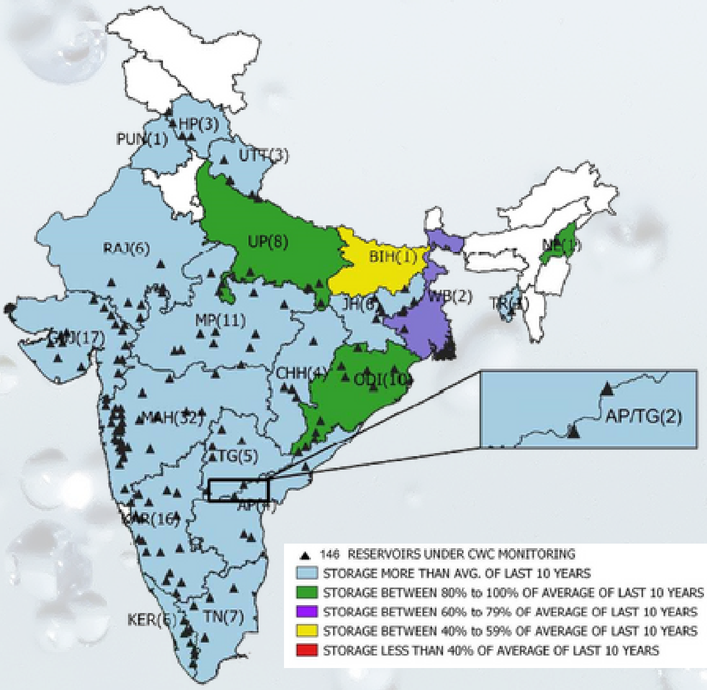

राज्यवार भंडारण स्थिति दर्शाने वाला मानचित्र (31.03.2023 तक)

31.03.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	159.3553	157.1637	98.62%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	11.640	11.6428	100.02%
3	Flood Management & Border Areas Programme (FMBAP)	11.3625	9.0703	79.83%
4	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	8.56	8.5556	99.95%
5	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	28.2716	26.8325	94.90 %
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	25.00	23.71	94.84%

16 से 31 मार्च 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान शपथ ली गई और स्वच्छता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

विश्व जल दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण भी हुआ।

श्री के वोहरा, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एवं श्री रिषी श्रीवास्तव मुख्य अभियन्ता का सरदार वल्लभभाई पटेल अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर G20 की पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक में सम्मिलित होने के लिए आयोजन समिति द्वारा माननीयगण का सांस्कृतिक रुप से स्वागत किया गया।

अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श के बारे में प्रेस को जानकारी देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

बांध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए *"आजादी का अमृत महोत्सव"* के अंतर्गत माही एवं तापी बेसिन संगठन, गांधीनगर के सहयोग से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) द्वारा सरदार सरोवर बांध, गुजरात पर दिनांक 25-03-2023 को संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ।

भारत यूरोपीय जल साझेदारी चरण- II के तहत एक हितधारक परामर्श बैठक 16.03.2023 को सीडब्ल्यूसी, गांधीनगर गुजरात में एमटीबीओ के मुख्य अभियंता श्री डी.एस.चस्कर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

13.03.2023 को एम एंड ईआरओ, के.ज.आ , भुवनेश्वर द्वारा कैप्तिपाड़ा ब्लॉक, मयूरभंज, ओडिशा में कालो नदी पर माछिया अर्जुन बांध पर नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री ए.के.मधोक, उप निदेशक, के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली और श्री संदीप, सहायक निदेशक, के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली शामिल हुए।

अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., शिलांग द्वारा मणिपुर में थौबल और धोलाईथाबी परियोजनाओं में सीएडी कार्यों का निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

- गर्मी से पहले ही नर्मदा की सहायक नदियां सूखने की कगार पर (राजस्थान पत्रिका, 03.03.2023)
- महिलाओं के योगदान के बिना जल संरक्षण और प्रबंधन संभव नहीं : मुर्मू (अमर उजाला, 05.03.2023)
- राजधानी में होली पर जल संकट — रेत माफियाओं की वजह से नहीं मिल रहा है पानी (दैनिक भास्कर, 08.03.2023)
- सतलुज—यमुना नहर विवाद का नहीं निकला अब तक कोई समाधान : केंद्र (अमर उजाला, 18.03.2023)
- गंगा की तर्ज पर यमुना नदी के लिए 'ई—प्रवाह' बने : समिति (जनसत्ता, 20.03.2023)
- गंभीर जल संकट की ओर झारखंड के कई जिले, अलर्ट मोड में सरकार (राजस्थान पत्रिका, 21.03.2023)
- 130 करोड़ लोगों को पानी देने वाली गंगा, सिंधु सहित 10 नदियों के सूखने का खतरा (दैनिक भास्कर, 24.03.2023)
- जल क्षेत्र में भारत 240 अरब डालर के निवेश को प्रतिबद्ध — जल शक्ति मंत्री शेखावत ने यूएन में कहा — पेयजल के लिए लागू कर रहे दो मिशन (अमर उजाला, 25.03.2023)
- गुरदासपुर में 500 करोड़ रुपए से रबर बांध बनाकर भारत रोकेगा पाकिस्तान जाने वाला पानी(दैनिक भास्कर, 27.03.2023)

इतिहास- सारदा सहायक परियोजना - पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान

सारदा सहायक परियोजना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्से के गरीबी से ग्रस्त और पिछड़े लाखों लोगों के लिए नई आशा लेकर आई है। 280.00 करोड़ रुपये की इस प्रतिष्ठित परियोजना का जून 1974 में चालू होना उनके अब तक के संकटपूर्ण अस्तित्व में एकमहत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

परियोजना

सारदा सहायक परियोजना में गैर-मानसूनी महीनों के दौरान सिंचाई के लिए इस नदी की अब तक की आपूर्ति को मोड़ने के लिए, कतर्नियाघाट, जिला बहराइच के पास घाघरा नदी पर एक बैराज के निर्माण की परिकल्पना की गई है और नदी सरदा की आपूर्ति का उपयोग करने के साथ ही गंगा-घाघरा दोआब बेसिन- जिसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, आज़मगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और ग़ाज़ीपुर जिले शामिल हैं, में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए सारदा नदी पर दूसरा बैराज,लखीमपुर के पास, जिला-लखीमपुर खीरी में निर्माण की परिकल्पना की गई। यह परियोजना 18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को 16 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई के साथ सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी।

मुख्य विशेषताएं

परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित मुख्य कार्य हैं:

(i) घाघरा नदी पर एक बैराज जिसमें नदी की आपूर्ति को लिंक चैनल में मोड़ने के लिए 18 मीटर की 35 खाड़ियाँ शामिल हैं।

(ii) घाघरा नदी के पानी को सारदा नदी में ले जाने के लिए 480 घन मीटर प्रति सेकंड की क्षमता वाला 28 किमी लंबा लिंक चैनल।

(iii) Aसारदा नदी पर एक बैराज जिसमें घाघरा और सारदा नदी की आपूर्ति को एक फीडर चैनल में मोड़ने के लिए 18 मीटर की 20 खाड़ियाँ शामिल हैं।

(iv)सारदा नहर प्रणाली के विभिन्न चैनलों में आपूर्ति पहुंचाने के लिए 260 किमी लंबा एक फीडर चैनल।

(v) वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण। इसमें मौजूदा चैनलों की 6,100 किमी लंबाई की क्षमता को तीन गुना से ग्यारह गुना तक बढ़ाना और 4,900 किमी नए चैनलों का निर्माण शामिल होगा।

चरण- I

सारदा सहायक परियोजना पर काम 1968-69 में शुरू किया गया था। दिसंबर 1971 में, परियोजना का दायरा काफी हद तक बढ़ा दिया गया था और इसके लाभों को बढ़ाने और उन्हें कई साल पहले लाने के लिए इसके निर्माण कार्यक्रम में भी तेजी लाई गई थी। परियोजना के पहले चरण में राज्य की प्रमुख नदियों में से एक, सारदा नदी पर बैराज बनाना और हेड से 105 किमी तक फीडर चैनल के साथ बड़ी संख्या में जल निकासी क्रॉसिंग, नियामक और पुल बनाना शामिल था, जिन्हें जून,1974 तक चालू करना निर्धारित किया गया था ताकि 1974-75 के दौरान सारदा नदी की आपूर्ति मोड़कर दरियाबाद शाखा प्रणाली पर 1.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा सके।

चरण-II

परियोजना के दूसरे चरण को जून 1975 तक पूरा करने का प्रस्ताव था, जिसमें घाघरा नदी पर बैराज, दो बैराजों के बीच लिंक चैनल और फीडर चैनल को 105 किमी से 119 किमी तक विस्तारित करना शामिल था ताकि सिंचाई आपूर्ति को बाराबंकी शाखा तक पहुंचाया जा सके और रबी और प्रारंभिक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए घाघरा के अब तक दोहन किए गए पानी का उपयोग किया जा सके।

1975 के दौरान 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता उत्पन्न की गई।

सारदा नहर प्रणाली

मौजूदा सारदा नहर प्रणाली को 1928 में हिमालय की तलहटी के पास बनबसा में सारदा नदी की आपूर्ति को मोड़कर मध्य उत्तर प्रदेश में गंगा-घाघरा दोआब में पड़ने वाले क्षेत्रों में सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। इस नहर प्रणाली का कमांड क्षेत्र 24 लाख हेक्टेयर है, लेकिन नहर क्षमता की सीमाओं के कारण, प्रणाली पूरे वर्ष पानी की भारी कमी से ग्रस्त रहती है और फसलों की

अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आवश्यक गहन सिंचाई प्रदान नहीं कर पाती है। औसत वार्षिक सिंचाई खेती योग्य कमांड क्षेत्र का केवल 33% है जबकि निचले इलाकों में यह केवल 19% है।

घाघरा बैराज

घाघरा बैराज में 45,518 वर्ग किमी के जलग्रहण क्षेत्र से डिजाइन बाढ़ निर्वहन को पारित करने के लिए 18 मीटर की 35 खाड़ियाँ शामिल हैं।

बैराज में तालाब का स्तर शुष्क मौसम के जल स्तर से 6 मीटर अधिक होगा। यह उच्च स्तर सारदा नहर प्रणाली की निचली पहुंच के अधिकतम संभावित क्षेत्र को सारदा सहायक परियोजना की कमान के भीतर लाने के लिए आवश्यक है।

इस बैराज का निर्माण 1970-75 के दौरान चार कार्य सत्रों में किया गया था।

बैराज पर पुल दिसंबर 1975 तक पूरा हो गया था और नदी की आपूर्ति को जनवरी 1976 में रबी सिंचाई के लिए बैराज की 24 खाड़ी में एक डायवर्जन कॉफ़र बांध की मदद से मोड़ने के लिए स्वीकार किया गया था क्योंकि तब तक केवल 11 गेट लगाए गए थे।

लिंक चैनल

28 किमी लंबे लिंक चैनल को बैराज के ठीक ऊपर सारदा नदी के बाएं किनारे तक पानी पहुंचाने के लिए 95 मीटर तल चौड़ाई और 4.1 मीटर पानी की गहराई के साथ एक अरेखित चैनल के रूप में डिजाइन किया गया है। लिंक चैनल का संरेखण पूरी तरह से घाघरा और सारदा नदियों के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है और कई जल निकासी को संपारित करता है, जिनमें से दो सुहेली और सोती नदियों के समपारण प्रमुख हैं। हालाँकि ये नदियाँ 2 किमी की दूरी पर लिंक चैनल को पार करती हैं लेकिन मध्यम से उच्च बाढ़ के दौरान वे पानी की एक शीट बन जाती हैं। दोनों नदियों को 4.5 मीटरx 4.5 मीटर आर.सी.सी. के 24 बैरल के माध्यम से नहर के नीचे उतारा गया है। सुहेली नदी के लिए बॉक्स प्रकार के अनुभाग और सोती नदी के लिए समान आकार के 12 बैरल बनाए गए है ।

लिंक चैनल में 100 लाख घन मीटर मिट्टी का काम, जो ज्यादातर स्प्रिंग लेवल के नीचे है और बड़ी संख्या में साइफन व पुल शामिल हैं जिन्हें तय समय के अनुसार दिसंबर 1975 में पूरा और चालू कर दिया गया था।

सारदा बैराज

सारदा बैराज, जिसमें 18 मीटर की 20 खाड़ियाँ शामिल हैं, को गैर-मानसून सीज़न के दौरान घाघरा नदी के पानी को ले जाने के लिए एक समतलपारक (लेवल क्रॉसिंग) के रूप में कार्य करना पड़ता है, जिसे लिंक चैनल द्वारा फीडर चैनल में पहुंचाया जाता है।

यह बैराज, बनबसा बैराज धारा के 160 किमी नीचे स्थित है। बनबसा में नदी का जलग्रहण क्षेत्र 14,800 वर्ग किमी और इस स्थल पर 17,680 वर्ग किमी है। इस पहुंच में 160 किमी की नदी घाटी समतल है जो पर्याप्त घाटी भंडारण प्रदान करती है।

बैराज की एक अनूठी विशेषता दाहिनी ओर एक गाद अपवर्जक, दो अंडर-स्लुइस बे (अंडरस्लुइस बे की कुल संख्या पांच) और हेड रेगुलेटर के 300मी अनुप्रवाह फीडर चैनल में एक गाद निष्कासक का प्रावधान होना है।

सरदा बैराज का पूरा काम दोनों रेगुलेटर और गाइड बांधों सहित एक ही कार्य सत्र में जून 1973 तक पूरा हो गया था।

फीडर चैनल

फीडर चैनल निचले सारदा बैराज के दाहिने किनारे से शुरू होता है और पुरवा शाखा के साथ अपने जंक्शन तक 260 किमी तक चलता है। यह कई अन्य छोटे चैनलों के अलावा मौजूदा सारदा नहर प्रणाली की पांच मुख्य शाखाओं को अतिरिक्त आपूर्ति प्रदान करता है। आपूर्ति प्रदान की गई मुख्य प्रणालियाँ हैं:-

(i) दरियाबाद शाखा 105 कि.मी. पर
(ii) बाराबंकी शाखा 119 कि.मी. पर
(iii) हैदरगढ़ शाखा 117 कि.मी. पर
(iv) रायबरेली शाखा 171 कि.मी. पर
(v) अंतिम भाग पर पुरवा शाखा।

निष्कर्ष

शारदा सहायक परियोजना का लक्ष्य 16,770 वर्ग किमी के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को 70 प्रतिशत सिंचाई सघनता के साथ सिंचित करना है। 258.80 किमी लंबा फीडर चैनल 650 घनमीटर/से के निर्वहन के साथ निचली शारदा बैराज के दाहिने किनारे से शुरू होता है, फिर आपूर्ति को शारदा नहर प्रणाली की विभिन्न शाखाओं, अर्थात् दरियाबाद शाखा, बाराबंकी शाखा, हैदरगढ़ शाखा, बरेली शाखा और पुरवा शाखा में भेजा जाता है।

शारदा सहायक परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 150 विकास खंडों में लाखों किसानों को 2 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक नहर सिंचाई प्रदान करती है।

(स्रोत: भागीरथ जनवरी 1976)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल
- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनिलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक (ज.प्र.अभि.)– सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in